

# द संडे व्यूज़

www.thesundayviews.com, www.indiaexpressnews.com twitter.com/sundayviews

लखनऊ से प्रकाशित

वर्ष : 10 अंक : 8

लखनऊ, रविवार, 17 सितंबर 2023

पृष्ठ : 08 मूल्य : 3/-

## भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व यूपी में 'दखल अंदाजी' बंद करे!

नवेद शिकोह

लखनऊ। घोसी का छोटा सा चुनाव हारना भाजपा की बड़ी चुनौती के संकेत हैं। लोकसभा चुनाव के सात- आठ महीने पहले ऐसे संकेतों को सुधार का मौका मिल जाने का सौभाग्य भी कहा जा सकता है। पेट्रोल कम बचा हो, गाड़ा रिजर्व में हो, आगे चलना है तो इंतजाम कर लीजिये...। ये जानकारी या चेतावनी भी महत्वपूर्ण होती है। घोसी के नतीजों ने बताया है कि भाजपा का पारंपरिक वोटर खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज के अच्छे खासे लोगों ने किन्हीं कारणों को लेकर भाजपा को वोट ना देकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती के मना करने के बाद भी दलित समाज के एक हिस्सा ने समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। पिछले करीब नौ- दस वर्षों के दरम्यान दलित समाज दो हिस्सों में बंटा है। बसपा और भाजपा पर इन्हें विश्वास है। मैनपुरी और फिर घोसी के उप चुनाव की बड़ी जीत के बाद लगने लगा है कि सपा ने बसपा और भाजपा के दलित वोट बैंक में संघे लगाने में सफलता हासिल करना शुरू कर दी है। दल बदलदुओं और आयात किये हुये नेताओं पर भाजपा विश्वास ना करे। छोटे-छोटे दलों के अलग-अलग जातियों के नेताओं के जाति केंद्रित बयानों से पिछड़ी जातियों की जनता प्रभावित नहीं होती, बल्कि सवर्ण समाज दलबदलुओं के बड़बोलेपन से भाजपा का साथ छोड़ने पर मजबूर हो सकता है। घोसी का नतीजा देखकर दलबदलुओं और बड़बोले नेताओं से जनता की नाराजगी देखकर सुभासपा चीफ ओमप्रकाश राजभर को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा साइड लाइन



करती है तो पूर्वांचल को खतरा होगा। और अगर राजभर पूर्वांचल का मोर्चा संभालते हैं तब भी खतरा। भाजपा को कोई बीच का रास्ता अपना पड़ेगा। बेहतर है कि जातिवादी नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में कमान देने के बजाय हिन्दुत्व और विकास के बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ पर ही केन्द्रीय नेतृत्व भरोसा करे। यूपी की जनता ने योगी का बुल्डोजर मॉडल पसंद किया है। दंगा मुक्त, माफिया मुक्त यूपी और अतीक, मुख्तार जैसे माफियाओं के खिलाफ शिकंजा भाजपा की बड़ी यूएसपी रही किंतु इसका उपयोग करने में पार्टी प्रचारकों को सहजता नहीं

रही। कारण ये कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा, और इस पार्टी का विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। यानी, तकनीकी तौर से माफिया मुख्यमंत्री अंसारी का बेटा एनडीए का हिस्सा हो गया। इंडिया गठबंधन का स्वरूप और माहौल भी घोसी में भाजपा की हार का कारण बना। इंडिया के तयशुदा पैटर्न पर सही मायने में यहां भाजपा के दारा सिंह चौहान के सामने सपा के सुधाकर सिंह मजबूती से लड़े। कुछ लोगों की धारणा रही है कि भाजपा को कोई हरा नहीं सकता।

शेष भाग पेज 7 पर



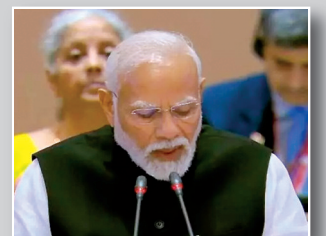
ओमप्रकाश राजभर के जन्मदिन पर विशेष

देखें पेज 03



सनातन धर्म का न आदि है और न ही अनंत...

देखें पेज 03



हमारा भारत जी-20 की झलकियां

देखें पेज 08

## लोकसभा चुनाव : यूपी की सियासत में 'मुल्ला' और 'चलनी' पर छिड़ गयी रार

संजय पुरबिया

लखनऊ। लोकसभा चुनाव की धमक ने राजनेताओं की धमनियों तेज कर दी है। मंच मिले या कैमरा ऑन हो जाये, फिर क्या जो मन भाया बोल दिया। यही वजह है कि चुनाव करीब आते-आते सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को 'जुबानी जंग' में खा जाने को आतुर दिखते हैं। बयानबाजियों का दौर अपनी रफ्तार में है जिसकी वजह से यूपी में सियासत का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा बयान देकर राजनीति के गलियारे में हलचल मचा दिया। केशव प्रसाद ने कहा कि 'नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है'...। बयान पर बौखलाये अजय राय ने आव देखा न ताव प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि भाजपा में 'सूप तो सूप, चलनियां और ज्यादा बोलती हैं'...। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि 'भाग्य ने बिना पात्रता के उन्हें पद पर बिठा दिया है'...। कम से कम मुंह खोलते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये...। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब मिर्ची सी तीखी बयानों का खूब दौर चलेगा और बयानवीरों की यहां कमी नहीं है। बात जो भी हो, 'मुल्ला' और 'चलनी' के बाद राजनीति के धुरंधर कितना मर्यादा लांघते हैं, इसे यूपी की सियासत के साथ-साथ जनता-जनार्दन देखने और सुनने को उत्सुक है।

लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है और बयानवीरों के बयान से यूपी में तपीश बढ़ती जा रही है।



क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, जुबानी तीर दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। उनके भाव से साफ लग रहा था कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से कांग्रेस प्रहार कर रही है, उसका



करारा जवाब देना है। उन्होंने सीधे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ बयान देते हुये कहा कि 'नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है'। प्रदेश में कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है। इसी के साथ ही उन्होंने आइएनडीआइए गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुये कहा कि चुनाव के पहले यह गठबंधन देश के माहौल को खराब करने पर तुला

हुआ है। बार-बार इस गठबंधन के नेता सनातन धर्म पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का बयान इंटरनेट पर वायरल हुआ विपक्ष फायर हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तिलमिला गये।

शेष भाग पेज 7 पर

## तीखी बात

## अनंतनाग के दंश : याद रहे यह बलिदान सैन्य अभियानों में चूक की न रहे गुंजाइश

एक ऐसे समय जब कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसों लेता दिख रहा है तब अनंतनाग की घटना सतर्क करने वाली है। यह घटना यही बता रही है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी किसी भी तरह कश्मीर को अशांत रखने के लिये हाथ-पांव मार रहे हैं। इसी कारण वे उन इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं जो लंबे समय से उनकी गतिविधियों से मुक्त थे। अनंतनाग में जिस आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारी सेना के दो बड़े अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसे केवल अंजाम तक ही नहीं पहुंचाया जाना चाहिये, बल्कि आतंकियों का खात्मा करके ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जाना चाहिये, जिससे वे भविष्य में इस तरह का दुस्साहस न कर सकें।

अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुये सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूँ बट का बलिदान देश के लिये एक बड़ी क्षति है। ये तीनों ही अफसर अपनी दिलेरी के लिये जाने जाते थे और उन्होंने अतीत में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिये और आतंकियों का चुन-चुनकर सफाया करने के साथ ही पाकिस्तान को नये सिरे से सबक सिखाया जाना चाहिये, क्योंकि जिस आतंकी गुट के आतंकियों के घात लगाकर किये गये हमले में हमारे बहादुर अफसर वीरगति को प्राप्त हुये, वह भले ही स्वयं को स्थानीय बताता हो, लेकिन उसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर का हर तरह का सहयोग एवं समर्थन हासिल है। वास्तव में इस आतंकी गुट को खड़ा करने का काम लश्कर ने ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के सहयोग से किया है, ताकि यह कहा जा सके कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कोई बड़ी घटना अंजाम देने की फिराक में रहे होंगे। एक ऐसे समय जब कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसों लेता दिख रहा है, तब अनंतनाग की घटना सतर्क करने वाली है। यह घटना यही बता रही है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी किसी भी तरह कश्मीर को अशांत रखने के लिये हाथ-पांव मार रहे हैं। इसी कारण वे उन इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं, जो लंबे समय से उनकी गतिविधियों से मुक्त थे।



वे दक्षिण कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस वर्ष अभी तक राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में लगभग 26 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी सीमा पर से घुसपैठ के लिये भी नए रास्ते चुन रहे हैं। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के साथ पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर और चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के दबे-छिपे समर्थकों के खिलाफ अभियान भी और तेज किया जाना चाहिये। इस पर भी फिर से ध्यान देना होगा कि आतंकियों के सफाए के किसी अभियान में सुरक्षा बलों को क्षति न उठनी पड़े। निःसंदेह ऐसे अभियान जोरिम भरे होते हैं, लेकिन इस पर और सावधानी बरतनी होगी कि अपने वीर जवानों को खतरों से कैसे बचाया जा सके? अतीत में आतंक विरोधी कुछ अभियान ऐसे रहे हैं, जिनमें आतंकियों का शीघ्र सफाया करने के प्रयत्न में हमारे जवानों को क्षति उठनी पड़ी।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के दो अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी व शुक्रवार को एक घायल जवान की मौत राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूँ बट की मौत बताती है कि आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान जहां खुफिया तंत्र को दुस्त करने की जरूरत है, वहीं रणनीति को अधिक धारदार व पुख्ता बने। दोनों ही सेना के अधिकारी आतंकवाद विरोधी इकाई का नेतृत्व करने वाले अनुभवी व सेना पदक का सम्मान पाने वाले थे। जाहिर है कि यह ऑपरेशन खुफिया सूचनाओं पर आधारित था, लेकिन कहीं न कहीं रणनीति के क्रियान्वयन में चूक हुयी है। पहले

सूचना दी गयी थी कि आतंकियों ने जंगल में अपना ठिकाना बना रखा है, लेकिन उन्होंने पहले ही घात लगाकर सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम को निशाना बना लिया। इसी चूक के चलते ही हमारे सैन्य अधिकारी व जवान आतंकवादियों के जाल में फंस गये। निःसंदेह, भविष्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपी के क्रियान्वयन में अधिक सतर्कता की जरूरत होगी। हालांकि, सेना ने वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर में ऐसे ऑपरेशनों के लिये अपने एसओपी में संशोधन किया था, जिसमें मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को आत्मसमर्पण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इसमें भटके हुए युवाओं को जान बचाने का मौका दिया जाता था लेकिन इस नीति ने सेना के जवानों के लिये लक्ष्य को कठिन बना दिया। निःसंदेह, ऐसी मुठभेड़ पे पहले मिली हुई सूचनाओं का गहन सत्यापन जरूरी होता है। आतंकवादियों व उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों की चौबीस घंटे की निगरानी जरूरी होती है। हालांकि, इस घटना से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी पर लाने की कोशिशों को झटका लगेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिये तैयार है। फिर भी इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद पहले से बहुत विलंबित चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से नहीं रोका जाना चाहिये।

बहरहाल, सेना व पुलिस के अधिकारियों की शहादत हमें सबक देती है कि अब खुफिया तंत्र की खामियों को दूर करने और ऑपरेशनों की मानक संचालन प्रक्रिया को मजबूत बनाने की जरूरत है। जिससे सेना के अधिकारी व पुलिसकर्मी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकें। निःसंदेह, हाल के दिनों में घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आयी है, लेकिन अभी भी आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की जरूरत है। कुछ समय पहले कुलगाम में हुयी एक मुठभेड़ के दौरान भी सेना के तीन जवान शहीद हुये थे। दरअसल, इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद ही काउंटर अभियान प्रारंभ किया गया था। इससे पहले मई में राजौरी में सैनिकों पर व पुंछ में सेना के टुक पर भी हमला हुआ था। यद्यपि पहले के मुकाबले में आतंकी हमलों की वारदात कम हुयी है, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि सेना के अभियान में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होती है।

## आत्मघात की विवशता : अभिभावक-समाज समझे किशोर मन

किसी भी समाज में किशोर नई संभावना और भविष्य की उम्मीद होते हैं। कोई भी समाज उनके बिना तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। एक युवा का असमय विच्छेद परिवार, समाज व देश के लिये असहनीय टीस है। किसी भी मौत को आंकड़ों की नजर से नहीं देखा जाना चाहिये। इसकी टीस उन मां-बाप से पूछी जानी चाहिये, जिन्हें वह जीवनभर का दर्द दे जाता है। किसी किशोर को भले ही यह आत्मघात समस्या से पार पाने का सरल रास्ता नजर आता हो, लेकिन इसकी कीमत परिवार-रिश्तेदार व समाज ताउम्र चुकाता है। बहरहाल, इस बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वह रिपोर्ट विचलित करती है, जिसमें उल्लेखित है कि पिछले एक दशक के दौरान देश में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 70 फीसदी बढ़ी है। जहां वर्ष 2011 में करीब साढ़े सात हजार छात्रों ने आत्महत्या की थी, वहीं वर्ष 2021 में आत्मघाती कदम उठाने वाले छात्रों का आंकड़ा 13 हजार से अधिक हो गया। वह भी तब कि जब हर आत्महत्या को दर्ज किया हो। अकसर देखा जाता है कि सामाजिक व कानूनी झमेलों से बचने के लिये आत्महत्या को प्राकृतिक मौत दर्शाने की भी कोशिश होती है। यह भी कि इन मामलों के आंकड़े ईमानदारी से दर्ज किये गये हों। बहरहाल, ये दुःखद ही कि कुछ फूल खिलने से पहले ही सदा-सदा के लिये मुरझा जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गला-काट स्पर्धा में फंस चुके ऐसे संभावनाशील छात्रों के मरने की खबरें राजस्थान के कोटा से आती हैं। जहां शेष भारत से सुनहरे सपने लेकर लाखों छात्र-छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिये आते हैं। मन के अनुकूल वातावरण न पाकर और भविष्य की आशंकाओं से घिरे कुछ छात्र मौत को गले लगाने को अंतिम विकल्प के रूप में देखने लगते हैं। कहीं न कहीं अपने परिजनों की उम्मीदों का बोझ ढोते ये छात्र इस बात से भयभीत होते हैं कि अपने मध्यम व निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लाखों के खर्च के साथ क्या वे न्याय कर पायेंगे?

दरअसल, देश में इंजीनियर-डॉक्टर बनने की जो भेड़चाल चल पड़ी है, उससे छात्रों को ये डर सताने लगता है कि वे यदि ये न बन सकें तो उनका जीवन व्यर्थ हो जायेगा। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उसकी विशिष्टता की पहचान करके उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिले। अपनी रुचि के विषयों में छात्र विशिष्ट करने में सफल होते हैं। वहीं दूसरी ओर आभासी दुनिया की भीड़ में ये छात्र अलग-थलग रहते हैं। जहां इनका संवेदनशील ढंग से व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। वहीं हम मानसिक रूप से इन बच्चों को इतना सशक्त नहीं बना पाते कि ये विषम परिस्थितियों में टूटकर न बिखरें। दरअसल, अब वे शिक्षक गिनती के ही रह गये हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास को अपनी प्राथमिकता बनाते हों। शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते कहीं न कहीं कक्षा में होने वाली पढ़ाई से इतर उन्हें कोचिंग्स की जरूरत बता दी जाती है। वहीं दूसरी ओर दूरदराज के इलाकों से अन्य भाषा में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर अंग्रेजी में पढ़ाई का दबाव भी होता है। उनकी काफी ऊर्जा अंग्रेजी सीखने में व्यय होती है। फिर वे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों से निकलने वाले छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाते। पिछले दिनों देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों एम्स व आईआईटी में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों की आत्महत्या करने की खबरें आई हैं, जो अपने पाठ्यक्रम के साथ कदमताल नहीं कर पाये। इस साल ही कोटा में करीब 24 छात्रों का आत्महत्या की राह चुनना इस संकेत की भयावहता को दर्शाता है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या को मनोवैज्ञानिक और संवेदनशील ढंग से संबोधित करने की कोशिश होती नजर नहीं आती। कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में यह भय जरूर रहता है कि मां-बाप ने लाखों रुपये खर्च करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, ऐसे में विफल होने पर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इस विकट समस्या के समाधान में अभिभावकों की बड़ी भूमिका हो सकती है। परिजनों-मित्रों द्वारा दिया गया संबल ही उन्हें आत्मघाती कदम उठाने से रोक सकता है।

## 'इंडिया' की अदालत में मीडिया

'कभी तेरे नाम से ही खबर पर ऐतवार होता था, आज तेरे लिखे पे नफरत फैलाने का इल्जाम है।' पत्रकारिता ने अपने महत्व को इतना गिरा दिया है कि अब बहस का विषय बनकर कोई एंकर कठघरे में खड़ा है। विपक्षी एकता के नाम पर बन चुका गठबंधन लोकतंत्र की गांठ से मीडिया के एक हिस्से को अलहदा करके आखिर कहना क्या चाहता है और यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुयीं कि 'कल तक जो हाशियों के बाहर कर रहे थे, आज अपनी ही महफिल से कट गये।' मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी चौपाल में हो रहे फैसलों का एक नज़ला अगर मीडिया पर गिर रहा है तो यह पत्रकारिता के गिरते मानदंड की चेतावनी भर नहीं, बल्कि भविष्य की मांद में एक खतरनाक आदेश पलने लगा है। मीडिया बनाम राजनीति का वर्तमान मुकाबला केवल 14 एंकरों का बहिष्कार नहीं कर रहा, बल्कि लोकतंत्र के तमाम स्तंभों के बीच जर्जर होते विश्वास, आपसी संतुलन और पारस्परिक भूमिका के क्षरण का भी संदेश दे रहा है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों में मीडिया खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी भाषा, शब्दावली, नैतिकता, संयम, विवेक, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक चरित्र को कहीं तो चोट पहुंचायी है, जिससे संपूर्ण पत्रकारिता में अस्थिरता, मौका परस्ती और कारपोरेटीकरण का बोलबाला हो गया। आश्चर्य यह कि कुछ चेहरे हाई प्रोफाइल या पंच सितारा पत्रकार बनकर, मीडिया व्यापार की पेशकश में कारिंदे हो गये। कुछ राजनीतिक बिचौलिये और कुछ समाज के भीतर नफरत के बीज बोने के माहिर हो गये।

पिछले सालों में जो मीडिया परिदृश्य उभरा है, उसमें पत्रकारिता ने अपनी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा में अत्यंत गिरावट के साक्ष्य सौंपे हैं। आज अगर विपक्षी गठबंधन की अदालत में मीडिया जगत के 14 चिन्हित चेहरे अखूत घोषित हो रहे हैं, तो यह असाधारण घटनाक्रम है और जिसके प्रभाव में पत्रकारिता के मनोबल को कहीं न कहीं चोट पहुंचेगी। विडंबना यह है कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की पार्टियां जहां



सत्तारूढ़ हैं, वहां भी पत्रकारिता से अपेक्षाएं भिन्न या स्वतंत्र नहीं हैं। मीडिया स्वतंत्रता की कीमत या तो किसी आपराधिक केस में उलझ कर चुकानी पड़ रही है या सरकारी विज्ञापनों से किनारे लगाकर मिलती है। लोकसभा में दी गयी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 2014-15 से दिसंबर 2022 तक प्रिंट मीडिया को 3138 करोड़ तथा इलेक्ट्रॉनिक को 3260 करोड़ के विज्ञापन बांटे हैं। जाहिर है इस धन का आबंटन मीडिया की छती पर नहीं, घुटने टेकने की वजह से कहीं अधिक हुआ है। लेकिन यही परिदृश्य अब राज्य सरकारें भी बना रही हैं। दिल्ली में आप सरकार अगर 600 करोड़ के विज्ञापन बांट कर अपना प्रचार करती है, तो मीडिया के बीच कतारबद्ध होने की वजह भी है। आज कोई सत्ता मीडिया को मजबूत होते नहीं देख सकती, तो दूसरी ओर पत्रकारिता में ऐसे लोगों और उद्देश्यों की भीड़ एकत्रित हो रही है, जो न

पेशेवर मानकों और न ही लोकतंत्र की जीवंतता के लिए संचालित होने का जज्बा रखते हैं। समाचार के उपभोक्ता स्वरूप में मीडिया को सशक्त आकार देने का सामर्थ्य समाज से भी गायब हो रहा है। समाज और व्यवस्था के बीच नाच रहा मीडिया खुद की ताकत गंवा रहा है, तो ध्रुवीकरण की आड़ में बहुसंख्यकवाद के गुनाहों से उसका हुलिया बदल चुका है। 14 एंकरों का बहिष्कार यह तो बता रहा है कि मीडिया के आंचल में कितनी बेहयाई और बेशर्मा है, लेकिन दुरुस्ती के लिये यह कार्रवाई कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कठघरे में खड़ी कर रही है। जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पतन कहीं गहरे तक है, लेकिन जब तक एंकरों के आका तक हाथ नहीं पहुंचेंगे, सत्ता से गलबहियां राष्ट्रीय स्तर से राज्यों की मिलकीयत तक जारी रहेंगी। बेहतर होगा इंडिया गठबंधन अपने राज्यों में मीडिया की स्वतंत्रता के लिये





## ओमप्रकाश राजभर के जन्मदिन पर विशेष टेम्पू चलाने से लेकर राजनीति के किंग मेकर बनने का सफरनामा

संजय पुरबिया

लखनऊ। वाराणसी के फतेहपुर खोदा सिंधौरा गांव का एक नौजवान बड़ा सपना लेकर गर्दीश के दौर में भी शिक्षा हासिल करता रहा। 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद राजनीति शास्त्र से परास्नातक की डिग्री भी हासिल की। हालात ये थे कि छात्र जीवन में अपना खर्च निकालने के लिये उस नौजवान को टेम्पू तक चलाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से उसने एक जीप खरीदा, जिस पर सवारियां ढोने का काम किया। आर्थिक तंगी का दौर था लेकिन उसने किसी काम को करने में संकोच नहीं किया क्योंकि उसमें खुददारी कूट-कूट कर भरी थी। उसके जेहन में जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर अपने लोगों को हक दिलाने का जुनून था। नौजवान में एक खास बात थी कि वो डंके की चोट पर सबसे सामने अपनी बात रखने का दम रखता था और उसके इसी अंदाज ने उसे राजनीति का एंग्रीमैन बना दिया। अपनी बेबाकी की वजह से आज वो राजनीति के पटल पर चमक रहे हैं और सभी राजनैतिक दलों की नींद उड़ा कर रख दिये हैं। एक आम शख्स से शख्तियत बने उस नौजवान का नाम ओमप्रकाश राजभर है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओमप्रकाश राजभर धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खुद बधाई दी है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओमप्रकाश राजभर का नाम इसलिये भी सत्ता पक्ष या यूँ कहें विपक्ष सम्मान से लेता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिये काफी है। साथ ही ओमप्रकाश राजभर के एंग्रीमैन स्टार्डिल से भी सभी राजनेता वाकिफ हैं, उनकी जुबां से निकले एक शब्द भी सत्ता के गलियारे में भूचाल ला देता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि हमेशा सुखियों में रहने वाले ओमप्रकाश राजभर की राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ



है। वे सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुये बल्कि गर्दीश के उन दिनों से रूबरू हुये, जिनके बारे में सोच कर भी हौसले पस्त हो जाते हैं। हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुखियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ है। राजभर मूल रूप से वाराणसी जिले के फतेहपुर खोदा सिंधौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज, बड़ागांव, वाराणसी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र से परास्नातक की डिग्री भी हासिल की। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिये यह टेम्पू चलाते थे। बाद में उन्होंने एक जीप खरीदा था, जिस पर यह सवारी ढोते थे। यह गांव में सब्जी की खेती भी किया करते थे। इनके परिवार में पत्नी राजमति राजभर के अलावा 2 पुत्र हैं, जिनका नाम अरुण राजभर और अरविंद राजभर है। दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। अरुण राजभर वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो अरविंद राजभर पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इनके पिता का नाम सन्नु राजभर है, जो कोयला खदान में काम करते थे?

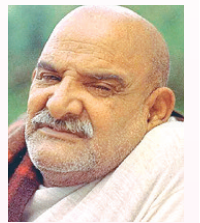
राजभर ने 1981 में बसपा के संस्थापक कांशीराम के साथ राजनीति शुरू की लेकिन 2001 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रिमो मायावती से विवाद के बाद उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया। दरअसल, राजभर भदोही का नाम बदल कर संतकबीर नगर रखने से नाराज थे। इसके बाद उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। 2004 से चुनाव लड़ रही भासपा ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किये लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाये। हालांकि वोट प्रतिशत अच्छा रहा। ओमप्रकाश राजभर ज्यादातर मौकों पर जीतने से ज्यादा खेले बिगाड़ने वाले बने रहें। लेकिन 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सत्ता के साथ रहने का सुख पा लिया। वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर बाद में पीछे हट गये थे। राजभर ने 35 सालों के संघर्ष के बूते अति पिछड़ों के नेता के रूप खुद को स्थापित किया। वे पूर्वांचल की दो दर्जन सीटों पर प्रभाव रखते हैं। कहा जाता है कि बसपा संस्थापक कांशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा।

ओमप्रकाश राजभर के मुताबिक पूरे देश में राजभर की आबादी 4 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 12 प्रतिशत है। एक आंकलन के अनुसार, पूर्वांचल के दो दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50 हजार से ढाई लाख तक हैं। वहीं, घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकरनगर, मछलीशहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही राजभर बहुल माने जाते हैं। इन सीटों पर राजभर समुदाय के लोग हार और जीत का निर्णय करते हैं।

ओमप्रकाश राजभर के राजनीतिक करियर का टर्निंग प्वाइंट तब आया जब पिछड़ी जातियों पर पकड़ को देखते हुये 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को 8 सीटें दी थी, इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके ओमप्रकाश राजभर की पार्टी ने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री बनाया।

## नीम करौली बाबा की कहानी, भक्त की जुबानी

लखनऊ के आशियाना में रहने वाले बाबा के भक्त की इच्छा थी कि वो नीम करौली बाबा के स्थापना दिवस 15 जून को जाकर बाबा का दर्शन करे। पूरा परिवार जाने की सोच



रहा था लेकिन घर की जिम्मेदारी को देख महिला अपने पति और दोनों बच्चों को बाबा का दर्शन कर आने की जिद करती रही। इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि कैसे नीम करौली बाबा का दर्शन करने जायेंगे। योजनाएं बन रही थी लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर में तय हुआ कि पति दोनों बच्चों के साथ बाबा का दर्शन करने जायेंगे लेकिन कैसे? बड़ा सवाल था लेकिन आस्था भी बाबा के प्रति भरपूर थी। अचानक पति के मित्र ने नैनीताल जाने और रहने की व्यवस्था करा दी। तय हुआ कि 14 जून की सुबह तीनों लोग बाबा का दर्शन करने कैचीधाम निकलेंगे लेकिन भोर में ही पति की तबीयत खराब हो गयी और तय हुआ कि बाबा का दर्शन करने पत्नी दोनों बच्चों साथ जायेंगी। सच में बाबा अपने भक्तों का चयन स्वयं करते हैं। तभी तो कार्यक्रम बदल गया और अचानक सभी व्यवस्था हो गयी। कैचीधाम पहुंचकर 15 जून की सुबह बाबा का दर्शन करने के लिये निकल पड़े लेकिन स्थापना दिवस होने की वजह से लाखों भक्तों की लंबी लाईन लगी थी। महिला अपने दोनों बच्चों के साथ भीड़ में लग गयी लेकिन पैर में दिक्कत की वजह से उन्होंने बाहर दूर से ही बाबा से फरियाद की कि बाबा भीड़ और पैर में दिक्कत होने की वजह से खड़ी नहीं हो पाऊंगी, क्षमा करियेगा कल दर्शन करने आऊंगी। महिला की दिली इच्छा थी कि आज ही बाबा का दर्शन कर प्रसाद के रूप में मिलने वाली पूजा ले ले लेकिन... मायूस होकर वो अपने बच्चों के साथ वापस लौटने लगी। तभी वहां आकर एक टैक्सी रुकी। वे लोग टैक्सी में बैठ गये। तभी चार युवक वहां आये और टैक्सी से आगे तक जाने का आग्रह करने लगे। उन लोगों को भी टैक्सी में बिठाकर महिला चल पड़ी। इसी बीच उनमें से एक भक्त ने पूछा बहन जी, क्या आपने बाबा का दर्शन कर लिया? इस महिला ने पूरी वाक्या बताया और कहा कि मेरी इच्छा थी कि बाबा का प्रसाद मिल जाता... लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। इस पर भक्त ने चार पुआ का पैकेट दे दिया और कहा कि नहीं इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, पूरा पुआ रख लीजिये। प्रसाद पाकर महिला खुश हो गयी और थोड़ी आगे जाने पर नैनीताल का रास्ता जाम की वजह से बंद कर दिया गया था। किसी ने बताया कि जब नीम करौली बाबा कैचीधाम आये थे तो सबसे पहले उन्होंने यहां नैनीताल में हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना की थी। पहले बाबा वहीं रहते थे। भक्तों ने बताया कि जब-जब कैचीधाम में भीड़ अधिक हो जाती थी तो बाबा वहीं चले जाते थे। महिला भी वहां दर्शन करने गयी। वहां मंदिर में एक बाबा बैठे थे, उन्होंने पूछा बिटिया प्रसाद मिला? महिला ने पूरा वाक्या बताया तो बाबा ने भी प्रसाद और चना दिया। महिला ने बताया कि नीम करौली बाबा के मंदिर में भक्तों को सिर्फ चना मिल रहा था। और मुझे यहां पूजा और चना दोनों मिल गया। भक्तों का कहना है कि बाबा पूजा के साथ चना भी खाते थे। ऐसा सुनकर भाव विह्वल होकर महिला ने बस इतना ही कहा नीम करौली बाबा की जय हो...। इसे नीम करौली बाबा का चमत्कार ही कहा जायेगा कि लाखों की भीड़ देख बेबस हुयी महिला और दोनों बच्चों ने जिस बेबसी से बिना बाबा का दर्शन किये और बिना प्रसाद लिये वापस लौट रहे थे, उन्हें बाबा ने कितनी आसानी से प्रसाद और चना दिला दिया। भक्त दिव्या ने बताया कि हमलोगों के पास कोई इंतजाम नहीं था लेकिन स्थापना दिवस के दिन जाने की बात में महीनों से कह रही थी कि बाबा का दर्शन करने जायेंगे। अचानक सारी व्यवस्था भी हो गयी और बाबा किसी ना किसी रूप में आकर प्रसाद और दर्शन भी दे गये। यही बाबा का चमत्कार है...।

## सनातन धर्म का न आदि है और न ही अनंत : राजनाथ सिंह

ब्यूरो

लखनऊ। सनातन धर्म पर अलग-अलग दलों के नेताओं के विवादित बयान आने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर हो रहा विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला धर्म है। यह धर्म जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को अपना परिवार कहने वाला धर्म है। इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इस पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है।

विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों पर तीखी प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का जहां तक प्रश्न है ये निर



नूतन क्षीर पुरातन है। यह एक ऐसा धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम का

संदेश देता है। यानि जाति, पंथ, मजहब और इन सबसे ऊपर है।

पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला सनातन धर्म है।

कहा कि सनातन धर्म का न आदि है और न ही अंत। दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। सनातन धर्म पर यदि संकट आया तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकट होगा मानव समाज के लिये होगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि फरवरी, मार्च के बाद लखनऊ की धरती पर ब्रह्मेस मिसाईल बनने का काम भी शुरू हो जायेगा। डीआरडीओ का कार्य भी जल्द पूरा होगा। इससे लखनऊ वासियों को लाभ मिलेगा। राम मंदिर के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही मंदिर का उद्घाटन होगा। उन्होंने ओवर ब्रिज निर्माण और गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये।

# अंतरिक्ष की खोज व मानवता का भविष्य?



रघु ठाकुर

नई दिल्ली। 24 अगस्त को इसरो ने चन्द्रयान-3 को चाँद पर उतार दिया और महत्वपूर्ण यह है कि इस बार चन्द्रयान-3 चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर उतारा, जहाँ पहली बार कोई यान पहुँचा है। वैसे तो दुनिया के अनेक देशों के यान चंद्रमा पर पहले भी पहुँचते रहे हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉंग पहली बार चाँद पर उतरे थे जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद लगभग 11 अन्य लोग भी चाँद पर पहुँचे हैं जिनमें रूसी भी शामिल हैं। हालाँकि चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने वाला पहला यान भारतीय है। इस क्षेत्र में यान को उतारना कठिन कार्य था क्योंकि साऊथ पोल के इलाके में काफी गड्ढे हैं और जिनमें सेफ लैंडिंग बहुत कठिन होता है। निःसंदेह यह सफलता इसरो के वैज्ञानिकों की है और जो बधाई के पात्र हैं।

भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से अंतरिक्ष में भेजा गया था और तभी से इस पर काम हो रहा था। आज वे दोनों महान वैज्ञानिक विक्रम सारा भाई और पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं हैं जिन्होंने इसरो को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। विक्रम साराभाई ने तो मात्रा रूपये प्रतिमाह के प्रतीकात्मक वेतन पर अनेकों वर्ष तक कार्य किया था, क्योंकि उस समय इसरो को शुरू करने की इबारत विक्रम सारा भाई लिख रहे थे। इसरो चीफ एस. सोमनाथ पूर्व चैयरमैन चन्द्रयान-2 का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक के.शिवन और इनके सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इस घटना ने विज्ञान के क्षेत्र एवं पूरी दुनिया में भारत को नई ऊँचाई दी है। मैं नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री को इसके लिये बधाई दूँगा कि उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को कभी भी निराश नहीं होने दिया। कुछ लोग चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग को राजनैतिक चरम से भी देखते हैं और बताते हैं कि इसरो की स्थापना प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। यह सही भी है तथा उन्हें भी इस समय याद करना सामयिक है परन्तु उनके नाम से नेहरू बनाम मोदी की प्रतिस्पर्धा खड़ी करना, यह उचित नहीं है। मैं श्री मोदी जी को इसलिये भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ब्रिक्स समिट से लौटकर सीधे इसरो का रास्ता पकड़ा और वैज्ञानिकों से मिलकर न केवल उन्हें बधाई दी बल्कि उनका एक अर्थ में उत्साह वर्धन भी किया तथा वर्ष 2019 में जब चन्द्रयान-2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पायी थी और तत्कालीन चैयरमैन शिवन के अक्षुण्ण चित्र अखबारों में छपे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इसरो के वैज्ञानिकों को जाकर प्रोत्साहित किया था और चन्द्रयान-2 की असफलता से निराश नहीं होने की सलाह दी थी।

भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये बजट आवंटन में भी लगातार वृद्धि करती रही है और पिछले पांच वर्षों में लगभग 67 प्रतिशत बजट की वृद्धि हुयी है। 2016-17



में जो बजट 7500 करोड़ का था वह अब 12500 करोड़ का है। पिछले वर्ष चंद्रयान मिशन की असफलता के बाद तो सरकार ने बजट को बढ़ाकर 13700 करोड़ कर दिया था जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। अब दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान में और अंतरिक्ष इकोनोमी में भारत को एक विशेष महत्व मिला है। तथा यह चन्द्रमा का अभियान और अंतरिक्ष की खोज का अभियान अब और आगे बढ़ेगा। यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद से रूस की भूमिका अंतरिक्ष अभियानों में बहुत सिकुड़ी है और कुछ अर्थों में चीन भी इसमें बहुत पीछे है। यानि, भारत का मुकाबला अमेरिका के नासा से है और यह भी एक सुविदित तथ्य है कि नासा में काम करने वाले विशेषतः महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले काफी वैज्ञानिक भारतीय या भारतीय मूल के हैं, जिनकी योग्यता व क्षमता से नासा प्रथम स्थान पर है।

स्पेस इकोनोमी की भी अब तेजी से बढ़ेगी और अनुमान यह है कि जो स्पेस इकोनोमी अभी 46400 करोड़ रूपया की है वह 2040 तक बढ़कर 8 लाख करोड़ रूपये की हो जायेगी। स्पेस स्टार्टअप भी शुरू हुये हैं और अनेक सम्पन्न लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी स्पेस अध्ययन के लिये पैसा खर्च कर रहे हैं। लगभग 30 हजार छोटे उपग्रह निजी तौर पर भेजे जाने की योजनायें हैं और 400 निजी कम्पनियां भारत में इनकी सहयोगी हैं तथा 140 निजी स्टार्टअप भी शुरू हुये हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री ने चन्द्रयान-3 की सफलता के बाद जो दो-तीन बातें कही हैं और इसरो के वर्तमान चीफ सोमनाथ ने भी जो कहा है उन्हें अनेक दृष्टिकोण से सोचना व उनका दूरगामी अर्थ समझना होगा:-

1. प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कहते थे कि 'चंदा मामा दूर के अब कहेंगे कि चंदा मामा दूर के'।
2. सोमनाथ ने कहा कि चांद का साऊथ पोल वैसे तो गड्ढों व गहरी खाई से भरा पड़ा है। लेकिन यहां कई तरह के खनिजों का भण्डार होने की संभावना है। दक्षिण पोल चंद्रमा का सबसे मूल्यवान हिस्सा है।
3. प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया है और इसरो ने भी कि अब मंगल गृह की ओर

भी ज्यादा ध्यान दिया जायेगा तथा सूर्य गृह के अध्ययन के लिये अब इसरो काम शुरू करेगा जो कि कर भी दिया है।

इसरो के मुखिया सोमनाथ ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि हमारे वेदों में अंतरिक्ष विज्ञान के सूत्र मिल जाते हैं। हालाँकि उन्होंने किसी वेद या रिचा का या किसी शास्त्र के नाम का कोई अलग से उल्लेख नहीं किया। वैसे भी हमारे देश में एक हिस्सा ऐसा है जो विज्ञान के हर कदम को अपने पुराने शास्त्रों व ग्रन्थों में होना बताता है। इन शास्त्रों व वेदों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर मेरा विशेष अध्ययन नहीं है। अतः इस पर कोई टिप्पणी मैं अधिकारिक तौर पर नहीं कर सकता, परन्तु एक बात अवश्य विचारणीय है कि जब अंतरिक्ष विज्ञान के और अन्य परमाणु शस्त्रों के सारे सूत्र वेदों व शास्त्रों में मंत्रबद्ध थे तो 3 हजार वर्ष या इससे अधिक से तो ये महाज्ञानी अभी तक चुप क्यों थे और उन मंत्र या सूत्रों का प्रयोग पहले ही क्यों नहीं किया? 1964 में इसरो की स्थापना हुई थी जिस पर अभी तक लगभग 70 हजार करोड़ रूपया खर्च हो चुका है, तब इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पिछले बार चन्द्रयान-2 जो असफल हुआ वह भी असफल नहीं होता और आज शायद दुनिया में सभी अंतरिक्षों के ऊपर भारत का झंडा फहरा रहा होता। हमें स्पेस साइंस यानि अंतरिक्ष विज्ञान आदि तकनीक को विदेशों से नहीं लेना पड़ता और इसरो तो दूर शायद नासा की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि भारत के वैदिक मंत्रों या शास्त्रों में वर्णित सूत्रों से हम लोग कब के सभी गृहों पर पहुँच चुके होते। मेरी समझ में विज्ञान एक निरंतर खोज का विषय है और इसे केवल अतीत या शास्त्रों के ज्ञान के भीतर खोजना या उसका दावा करना तर्क संगत नहीं है।

यह भी दुनिया से समाचार आ रहे हैं कि मून मिशन पर अब दुनिया अधिक काम करेगी क्योंकि मंगल गृह मानव को रहने के लिये ज्यादा उपयुक्त है। यह भी कहा जा रहा है कि मंगल गृह के लिये अन्य जरूरतों की पूर्ति चन्द्रमा के माध्यम से हो सकेगी। और ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया के ताकतवर और विज्ञान में अग्रणी देश इन गृहों

का इस्तेमाल मानव की रिहाईश के लिये और अपने हथियारों के अड्डे बनाने के लिये करने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी परंतु अंतरिक्ष व गृहों की खोज अगर इन भावनाओं व उद्देश्यों से की जा रही है तो यह मानवता के लिये बहुत खतरनाक हो सकता है।

1. अगर बढ़ती आबादी की जरूरतों की पूर्ति के लिये दुनिया अंतरिक्ष व गृहों का प्रयोग करेगी तो ये गृह या अंतरिक्ष कितने समय तक इसकी पूर्ति कर सकेंगे?
2. अगर युद्ध और शक्ति के लिये या दुनिया पर नियंत्रण के लिये इन गृहों का प्रयोग होगा तो क्या यह दुनिया बच सकेगी और गृह बच सकेंगे? विकास के यह नये चरण कहीं दुनिया के विनाश का कारण तो नहीं बन जायेगे।
3. आज पृथ्वी, सूर्य चन्द्रमा व अन्य गृहों से जिस प्रकार संबंधित व प्रभावित होती है वह दुनिया व मानवता के लिये बहुत उपयोगी है। सूर्यास्त के बाद रात्रि का आगमन व चाँद का दिखना यह इंसान को प्रखर गर्मी व धूप से राहत प्रदान करता है परन्तु जब चाँद ही एक वैकल्पिक धरती बन जायेगी, तब क्या चन्द्रमा की वह भौगोलिक स्थितियां रहेंगी जो आज हैं और क्या दुनिया का पृथ्वी व सूर्य के सम्बन्धों का चक्र यथावत रहेगा या बदलेगा? एक क्षण को कल्पना करें कि चन्द्रमा नहीं है, और 24 घंटे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़े तो क्या पृथ्वी जिंदा रहेगी? क्या मानव जिंदा रहेगा?
4. अगर आबादी आज के हिसाब से बढ़ती रहे तो यह गृह भी कितने आबादी की आवासीय पूर्ति कर सकेंगे। क्या यह भी कोई स्थायी या तार्किक विकल्प होगा? आज दुनिया को कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहिये। अपनी आबादी को हमें न्यूनतम करने का सोचना चाहिये।
5. अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच चन्द्र न रहे तो क्या समूची दुनिया रेगिस्तान, और जल व वृक्ष विहीन नहीं हो जायेगी? यह कहा जा सकता है कि गृहों को धरती के चारो ओर चक्र लगाने का क्रम यथावत रहेगा, परन्तु तब क्या इन

गृहों पर इंसान का जीवन रह सकेगा? 6. अगर ये नये खोजे जा रहे गृह युद्ध के लिये या सुरक्षित हथियारों के प्रयोग के लिये उपयोग किये जाते हैं तो फिर तो दुनिया की एक बड़ी आबादी का बचना क्या संभव होगा?

7. तब क्या यह दुनिया लोकतांत्रिक दुनिया रहेगी या फिर अंतरिक्ष के नये शक्तिमान की प्रजा बन जायेगी।

8. विज्ञान का विकास मानवता के लिये होना चाहिये ना कि मानवता की हत्या के लिये। यह प्रश्न अकेले भारत के नहीं है बल्कि समूची दुनिया के लिये हैं? और अच्छा हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी अंतरिक्ष की खोज व मानवीय जीवन जैसे प्रश्नों पर विचार करना शुरू करे तथा विज्ञान संगत मानवीय दुनिया का निर्माण कैसे हो इस पर विचार करें?

मैं जानता हूँ कि मेरे इस लेखन व कथन को कुछ गलत भी समझा जा सकता है। और विशेषतः सत्ता प्रशंसक, विज्ञान भोगी, धन विपासु और अतीत जीवी लोग इन्हें कुछ भिन्न रूपों में देखेंगे या इसे आलोचना मानेंगे परन्तु मैं आलोचना के लिये यह सब नहीं लिख रहा हूँ बल्कि आने वाले 100-200 वर्षों के बाद जब मैं व हममें से बहुत से लोग भी नहीं रहेंगे और इसे पढ़ने वाले भी नहीं रहेंगे पर तब भी यह दुनिया सुरक्षित बची रहे, प्रकृति व मानवता सुरक्षित रहे, इंसान-इंसान रहे और एक लोकतांत्रिक विश्व बना रहे। मैं इन भावनाओं के साथ यह लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि, कुछ कथावाचक चन्द्रमा पर पहली कथा वाचन कर खुश होंगे। कुछ अति संपन्न लोग, अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करेंगे। कुछ नवधनाइय व्यक्ति अपने बच्चों की शादी चाँद या मंगल गृह पर आयोजित कर खुश होंगे। कुछ पांच सितारा से सात सितारा होटल वाले भी अपने व्यवसाय को लेकर खुश होंगे पर क्या यह दुनिया सुखी व सुंदर बनेगी? जल-वायु परिवर्तन तेजी से प्रकृति व मानव के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है और अभी यह परिवर्तन व घटनायें केवल वर्तमान पृथ्वी की घटनाओं को लेकर हैं। अंतरिक्ष, मंगल, सूर्य व ऐसे अनेकों गृह अभी दुनिया की जलवायु और जीवन को सुरक्षित उपयोग के माध्यम हैं, परन्तु जिस दिन यह गृह कमाई, लूट और ताकत का माध्यम बनें, उस दिन की दुनिया की कल्पना कठिन है। आशा है कि वे अतीत प्रेमी और शास्त्रों व वेदों के जानकार भी मेरी इस चिंता के साझीदार और सही विचारक बनें साथ ही विज्ञान का निरंतर अपनी सुख व सुविधा भोग व ताकत के लिये बेरहम इस्तेमाल करने वाली नई पीढ़ी जो अब न केवल विज्ञान व तकनीक भोगी है बल्कि तकनीक आश्रित बन रही है, भी इन प्रश्नों को गंभीरता से सोचेगी। इसरो के वर्तमान मुखिया सोमनाथ ने केरल के बलमंगलम में अपना घर बनाया है। और यह बलमंगलम केरल के सुरम्य वन आरक्षित क्षेत्र में है। क्या सोमनाथ जी भावी दुनिया को बलमंगलम के रूप में देखना चाहेंगे या नये उभरते-प्रदूषण, जल-वायु, खान-पान, में जहर देते महानगरों के रूप में? यह एक स्थापित सच है कि जिस व्यक्ति ने अणु बम की खोज की थी, बाद में उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराये जाने के बाद सार्वजनिक रूप से दुःख प्रायश्चित्त व बोझ सहित स्वीकारा कि मेरी खोज का यह परिणाम होगा तो शायद मैं यह अणुशक्ति खोजने का प्रयास नहीं करता। कभी ऐसा न हो कि किसी दिन दुनिया के नासा-इसरो के या अन्य वैज्ञानिक भी पश्चाताप करने को विवश हो जायें कि अंतरिक्ष की खोज उनकी भूल थी, उसका उत्तर न केवल उन्हें बल्कि दुनिया के समूचे वैज्ञानिकों को देना है।





रेलवे अफसर रिश्वतखोरी कांड: अफसर नहीं डकैत है के.सी. जोशी

## भ्रष्टाचार के इस खेल में कई बड़े अफसर भी नपेंगे

अनंत सक्सेना

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक कार्यालय में ठेकों के लिये ही रिश्वत ही नहीं, बल्कि कई तरीकों से अवैध कमाई का खेल चल रहा था। चर्चा है कि जिम्मेदारों ने कबाड़ घोषित की गयी एक कार के नाम पर लंबे समय तक तेल और ड्राइवर के भत्ते के नाम पर लिया गया भुगतान भी अफसरों की जेबों में गया। इसकी शिकायत भी हुयी है। सीबीआई की टीम ने इससे जुड़ी कई फाइलें भी जब्त कर ली हैं। जांच की आंच में डीएस 8, निष्प्रयोज्य वाहन के लिये फार्म के आने से कई और घोटाले का राज सामने आ सकता है।

रेलवे में पहले विभागीय गाड़ियां होती थी। बाद में सारे विभागों में अनुबंध के तौर पर अधिकारियों को गाड़ियां उपलब्ध करायी गयी। बताया जाता है कि स्टोर डिपो में एक कबाड़ घोषित हो चुकी कार के नंबर पर तेल और ड्राइवर के वेतन का भुगतान लिया गया है। जिस अधिकारी की शह पर यह खेल चल रहा था वह भी



के.सी. जोशी का खास है। वहीं, रेल महकमे में चर्चा है कि भ्रष्टाचार के खेल में सिर्फ दो अफसरों की लड़ाई ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई और मजबूत लोग हुये हैं। के.सी. जोशी की एक और बड़े अफसर से अनबन चल रही थी। वहीं, दिल्ली से आयी विजिलेंस की टीम में 77 ठेके एक ही फर्म को देने के मामले में भी अफसरों में तनातनी बढ़ गयी थी। हालांकि उस अफसर को हटवाने में के.सी. जोशी कामयाब रहा लेकिन चर्चा यह भी है कि जोशी पर रिश्वत का आरोप लगाने वाला प्रणव त्रिपाठी हटाये गये अफसर का खास है। उस अफसर ने अपने कार्यकाल में प्रणव

की मदद की थी। अब दोनों अफसर और उनके लोग आमने-सामने आ गये हैं। लिहाजा अब कई और काली करतूतों से पर्दा हट सकता है। रेल महकमे में बातचीत का एक चैट वायरल हुआ है। इसमें लिखा गया है कि सर, पीसीएमएम, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक आपके रेलवे बोर्ड विजिलेंस केस के लिये पांच लाख मांग रहे हैं। बोले हैं मैंनेज के लिये दो नहीं तो सब गलत, बरबाद कर दूंगा। जवाब में लिखा गया है कि साहब को मैं डेला भर कुछ नहीं दूंगा। मैंने कोई गलती नहीं की है। साहब मुझसे कुछ गलत करवाना चाहते थे तो मैंने नहीं किया। बट भगवान सब देखता है, जय

महाकाल। बताया जा रहा है कि यह चैट एक रेल अफसर व ठेकेदार का है।

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक के.सी. जोशी ने उत्पादन इकाइयों में ही ज्यादातर नौकरी की है। इस ओर लोगों का ध्यान कम जाता है और यहां सीधे ठेकेदार से सेटिंग करना भी आसान है। वैसे भी इस विभाग को रेलवे में मलाई वाला कहा जाता है। चर्चा है कि एक बार इनका ट्रांसफर पश्चिम रेलवे में हो गया लेकिन आदेश जारी होने के बाद के.सी. जोशी ने ज्वाइन नहीं किया और एक बड़े अफसर को साधकर पूर्वोत्तर रेलवे में पोस्टिंग करा ली।

## फतेहली का तालाब में छत गिरने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत आखिर कंडम मकान में बिजली का कनेक्शन किसने दिया? पांच लोगों के मौत का कौन है जिम्मेदार?



संजय पुरबिया

लखनऊ। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की फतेहअली रेलवे कॉलोनी में शनिवार की रात साढ़े तीन बजे एक मकान की छत ढह गयी जिससे पांच लोगों की दब जाने से मौत हो गयी। एक ही परिवार के पांच लोग कब मौत की चादर ओढ़ दफन हो गये, पड़ोसियों को भी पता नहीं लगा। अलसुबह जब लोगों की नींद खुली तो वहां का नजारा देख सबकी सांसें हलक में आ गयी। चीख-पुकार का मंजर और पुलिस, एनडीआरएफ के अलावा रेलवे के अफसरों की चहल-कदमी की गूंज से पूरा इलाका थरा गया। जिसने सुना वो घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा। बता दें कि फतेहअली का तालाब कालोनी में लगभग 200 परिवार रहता है। अधिसंख्य मकान जर्जर हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग विभाग ने कंडम घोषित कर दिया है। बावजूद इसके वहां पर रेल कर्मचारी और किरायेदारों को परिवार रह रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जब रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने मकान को कंडम घोषित कर दिया तो उसे रेलवे पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मिलकर खाली क्यों नहीं कराया? सवाल यह भी है कि कंडम मकानों में बाहरी लोगों को किरायेदार के रूप में किसने रखा और कितनी कमाई कर रहा है? बड़ा सवाल यह है कि जब

मकान कंडम है तो उसमें बिजली का कनेक्शन किसने और किस नियमावली के तहत दिया है? बता दें कि रेलवे में इंजीनियरिंग और बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कंडम मकानों में बड़ी संख्या में रेल कर्मी और किरायेदार रह रहे हैं। अधिकारियों की मानें तो पूर्व आईओडब्ल्यू स्टेट एस.सी.द्विवेदी ने कंडम मकानों में बड़ी संख्या में किरायेदारों को रखकर मोटी रकम वसूल करते रहे। इसी तरह, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज ने कंडम मकानों में बिजली कनेक्शन देने के एवज में बड़ी रकम वसूल कर अपनी जेब गरम कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ फतेहअली का तालाब कालोनी का ही नहीं बल्कि पंजाब नगर, बरहा, मुनवरबाग, एलडी कालोनी सहित चालीस क्वार्टर का भी है। सभी कालोनियों की जांच करा ली जाये तो पूर्व आईओडब्ल्यू स्टेट और इलेक्ट्रिकल इंचार्ज के भ्रष्टाचार की कहानियां खुद-ब-खुद सामने आ जायेंगी। आखिर में फिर एक सवाल करूंगा कि फतेहअली का तालाब कालोनी में मरने वाले पांचों बेगुनाह के मौत के लिये जिम्मेदार कौन है? अभी भी समय है, यदि डीआरएम नहीं चेतें तो आगे भी बेगुनाह लोग बेमौत मारे जायेंगे। फतेहअली का तालाब रेलवे कालोनी में बारिश के बाद मकान और कमजोर हो गया था। सुबह सफाईकर्मियों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। टीम ने मलबा हटाकर पांच लोगों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिये लोकबंधु अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और सुबह लोगों का तांता लग गया, जिसे संभालने के लिये और पुलिस बुलानी पड़ी। मृतकों में सतीश चंद्र 40, सरोजनी देवी 35, हर्षिता 13, हर्षिता 10 और अंश 5 शामिल हैं। डीसीपी पूर्व हृदेश कुमार ने बताया कि पुरानी रेलवे कॉलोनी में घर की छत ढह गयीय जिससे एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी है। शवों को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की फतेहअली कॉलोनी में करीब 200 परिवार रहते हैं। कॉलोनी के ज्यादातर मकान जर्जर हैं और कंडम घोषित किये जा चुके हैं। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन ने लोगों से मकान खाली नहीं करवाये और लोग रह रहे हैं। जिसके चलते हादसा हुआ। जिस मकान की छत गिरी उस वक्त मकान में पांच लोग थे, जिनकी मौत मलबे में दबने से हुई है। सतीश चंद्र के पिता रामचंद्र पहले रेलवे में थे जिनकी मृत्यु के बाद मां का भी निधन हो गया और सतीश चंद्र को अनुकंपा पर नौकरी मिलने की उम्मीद थी। सतीश अपने परिवार के साथ यहां रहते थे जबकि सतीश के भाई अमित भी रेलवे में हैं।

हादसे पर डिटी सीएम ब्रजेश पाठक ने गहरा दुःख जताते हुये त्वरित राहत कार्य के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे का यह मकान काफी पुराना था। डिटी सीएम ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार के शेष परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जायेगी

पूर्व आईओडब्ल्यू स्टेट की शह पर बरहा, फतेहअली का तालाब, मुनवरबाग, एलडी कालोनी में रखे गये हैं किरायेदार?

शासन से सवाल : क्या कमांडेंट मनीष दूबे किसी का रेप करेगा तब आप मानेंगे की ठोस प्रमाण है!

## क्या एसीएस अनिल कुमार दागी कमांडेंट मनीष दूबे को बचा रहे हैं!

संजय पुरबिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तथाकथित नौकरशाहों की माया निराली है। ये भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबे और परायी महिलाओं की अस्मत् लूटने की चाह रखने वाले अफसरों पर मेहरबान दिखते हैं। आप जानते हैं कि होमगार्ड विभाग के कमांडेंट और एसडीएम ज्योति मौर्या के अवैध संबंधों को लेकर उसके पति आलोक मौर्या के बयान पर राजनीति से लेकर देशभर के परिवारों में भूचाल आ गया था। पति को धोखा देकर पराये मर्द से संबंध बनाने की बात सुन पूरे देश में ज्योति मौर्या और मनीष दूबे के प्रति गुस्सा सुलगने लगा था। शासन की सख्ती के बाद होमगार्ड विभाग के डीजी बी के मौर्या ने जांच प्रयागराज के डीआईजी संतोष सुचारी को सौंपी। डीआईजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि गाजीयाबाद के कमांडेंट मनीष दूबे के खिलाफ अमरोहा की महिला होमगार्ड संकेत कुमारी ने गंभीर आरोप लगाते हुये कहा है कि मनीष दूबे यहां तैनाती के दौरान उसे अकेले में बुलाते थे। ना जाने पर उसे सस्पेंड कर अपने गुर्गों से आने का दबाव बनाते थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मनीष दूबे ने ज्योति मौर्या को व्हाट्सअप चैटिंग में बिना नाम लिये उनके पति को रास्ते से हटाने की बात अपने मोबाइल नंबर से किया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मनीष दूबे जब गाजीयाबाद में कमांडेंट के पद पर तैनात था तो बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये लखनऊ आकर फाईव स्टार होटलों में ठहरता था, जबकि उसका लखनऊ में निजी आवास है। बाकी छोड़िये, इन तीन मुद्दों पर क्या कमांडेंट मनीष दूबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिये ?

**सवाल नंबर 1-** कमांडेंट मनीष दूबे जब अमरोहा में तैनात थे तो महिला होमगार्ड संकेत कुमारी को वो अपने घर पर खाना बनाने के लिये बुलाते थे। संकेत ने घर जाकर खाना बनाने के लिये मना कर दिया, इस पर मनीष दूबे उसे अकेले में मिलने के लिये

बुलाने लगे। इस बात को भी संकेत कुमारी ने खारिज कर दिया तब बौखलाये मनीष दूबे ने उसे बेवजह सस्पेंड कर दिया। उसने सोचा होगा कि ऐसे नहीं आयी तो बहाली कराने के लिये आयेगी और फिर...। संकेत कुमारी उसके पास जाने की बजाये डीजी, होमगार्ड से मिली और लिखित शिकायत की। पूर्व डीजी, विजय कुमार ने तत्काल फोन कर मनीष दूबे को संकेत कुमारी को बहाल करने का निर्देश दिया, तब जाकर उसकी बहाली हुयी। नियम है कि डीजी के कहने के बाद तीन माह बाद कमांडेंट ने उसकी बहाली की। नियमतः एक माह के अंदर संकेत कुमारी को बहाल कर देना चाहिये था। डीजी के आदेश को नजरअंदाज करने पर उसी समय कमांडेंट मनीष दूबे को निंदा प्रविष्टि तो देना ही चाहिये था, जो नहीं किया गया। खैर, संकेत कुमारी का बयान ही काफी है मनीष दूबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिये। भरोसेमंद अधिकारियों ने बताया कि संकेत कुमारी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन संकेत अपने इंसाफ के लिये हर लड़ाई लड़ने के लिये तैयार है।

**सवाल नंबर 2-** ज्योति मौर्या के व्हाट्सअप पर कमांडेंट मनीष दूबे ने लिखा है कि रास्ते से हटा दो, कहानी खत्म कर दो...। इस पर डीआईजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर पुलिस विभाग द्वारा मनीष दूबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गयी है।

**द संडे व्यूज** ने सबसे पहले व्हाट्सअप चैटिंग का खुलासा कर बताया था कि मनीष दूबे और ज्योति मौर्या मिलकर पति आलोक मौर्या के हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात आलोक मौर्या ने भी चैनल के सामने कहा है। ये डॉयलॉग मनीष दूबे ने अपने मोबाइल नंबर से ज्योति मौर्या के मोबाइल नंबर पर किया था। क्या मनीष दूबे के खिलाफ होमगार्ड विभाग को सस्पेंड कर विभागीय जांच नहीं बिठानी चाहिये?

**सवाल नंबर 3-** गाजीयाबाद का कमांडेंट बनने के बाद आये दिन मनीष दूबे शहर से बाहर बिना किसी अधिकारी को बताये गायब रहते थे। कई बार

अधिकारियों का दौरा होता था और दूबे जी गायब मिलते थे। मनीष दूबे आये दिन लखनऊ के पांच सितारा होटलों में किसी महिला के साथ रुकते थे, जबकि यहां पर उनका निजी आवास भी है। यदि मनीष दूबे अवकाश पर थे तो क्या किसी सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत करा रखे थे? देखा जाये तो मनीष दूबे ने साबित कर दिया कि उसकी नजरों में शासन और मुख्यालय के अफसरों की कोई अहमियत नहीं है। तभी तो नियमों को तार-तार कर वो भ्रष्टाचार और किसी का परिवार बर्बाद करता रहा और विभागीय नौकरशाह धुराराष्ट्र बनकर तमाशा देखते रहे और आज भी मूक बने हुये हैं लेकिन होमगार्ड विभाग के अपर प्रमुख सचिव (एसीएस) अनिल कुमार ने कमांडेंट मनीष दूबे को लेकर मीडिया में बयान दिया है जिससे वे खुद सवालियों के घेरे में आ गये हैं। सुनिये, अनिल कुमार का मीडिया में बयान- शासन की जांच में मनीष दूबे पर अनियमितता करने अथवा विभाग की छवि धूमिल करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है...। अनिल जी, शासन में बैठे ताकतवर नौकरशाह या आपकी नजरों में ठोस प्रमाण क्या है? मनीष दूबे अपने अधीनस्थ काम करने वाली महिला होमगार्ड को अकेले में क्या आरती उतारने के लिये बुला रहा था? क्या संकेत कुमारी का बयान ठोस प्रमाण नहीं है? ज्योति मौर्या के व्हाट्सअप पर उसके पति आलोक मौर्या के मर्डर की प्लानिंग करने की योजना बनाना ठोस प्रमाण नहीं है? क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बिना अवकाश लिये लखनऊ के 5 स्टार होटलों में किसी महिला के साथ ठहरने का सबूत ठोस प्रमाण नहीं है। आखिर में मेरा सवाल सरकार के काबिन बनने वाले उन नौकरशाहों से है कि क्या उनके परिवार की महिलाओं, बेटियों पर यदि उनके साथ काम करने वाला कोई अधिकारी मनीष दूबे जैसी गंदी निगाह रखे तो आपलोग क्या करेंगे? यदि आपके घर की महिलाएं या बेटियां शिकायत करेंगी तो भी आप उनसे ठोस सबूत मांगेंगे?



## पहले से घाटे में चल रहे सहकारी बैंक अब 98 करोड़ के लाभ में चल रहे हैं: जे.पी.एस.राठौर

लखनऊ। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि उ.प्र. सहकारिता बैंक आज बेहतर ढंग से काम कर रहा है। अब सहकारी बैंक विकास की राह पर चल पड़े हैं। 15 साल से घाटे में चल रहे

सहकारी ग्राम विकास बैंक को 98 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। पिछले पांच सालों में बैंक का कुल व्यवसाय 12 हजार करोड़ से बढ़कर 22000 करोड़ रुपये हो गया है। दो वर्षों में 13 नई शाखाओं को आधुनिक परिवेश में

स्थापित किया गया है। 243 नई शाखाओं को सत्र में चालू करने की तैयारी है। इस समय 7500 सहकारी समितियां हैं। कोशिश यह है कि प्रदेश के हर गांव में एक-एक सहकारी समिति खोली जाये। बताया कि कुछ सालों पहले तक 16 सहकारी बैंकों का लाइसेंस निरस्त होने वाला था। न केवल उनको बहाल रखा गया बल्कि उनमें से 11 को घाटे से उबारा गया। अब पांच रह गये हैं उन्हें भी घाटे से बाहर

निकाल लिया जायेगा। 32 प्रकार के नये काम बैंक को दिये गये हैं। श्री राठौर ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक ही परिवार का कब्जा रहता था लेकिन अब इनके लिये सभी को जिम्मेदारी मिल रही है। इस चुनाव में इसी तरह से परिणाम आये हैं। अब विपक्ष मीटिंग कर रहा है। वे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है।



## किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार



कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से

## मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

### आवेदन

कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में विधिक वारिस/वारिसों/स्वयं कृषक के द्वारा आवेदन पत्र जिलाधिकारी को सम्बोधित करते हुए सम्बन्धित तहसील में जमा किया जाएगा।

दुर्घटनावश मृत कृषक के एक से अधिक वारिस होने पर उनके द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जाएगा।

### पात्रता

खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार एवं खातेदार/सहखातेदार के परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है।

ऐसे भूमिहीन व्यक्ति, जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं तथा जिनकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गयी भूमि पर कृषि कार्य है।

कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को उसकी आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।

### योजना का आच्छादन

प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना एवं अन्य किसी कारण से कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता होती है, तो कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता के प्रकार, प्रकृति इत्यादि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता यदि आत्महत्या या आपराधिक कार्य करते समय होती है, तो ऐसी दशा में इस योजना के अन्तर्गत उसे कोई सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

## योजना हेतु प्राविधानित धनराशि एवं लाभार्थियों की संख्या

वित्तीय वर्ष	शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
2020-2021	500.00	11,275
2021-2022	600.00	13,645
2022-2023	650.00	15,231

वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 750 करोड़ रुपये का प्रावधान





## भयानक बाढ़ से दो भागों में बंट गया लीबिया का डर्ना शहर, कभी कहा जाता था धरती का 'स्वर्ग'



लीबिया के डर्ना शहर में एक विनाशकारी बाढ़ से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बाढ़ से लगभग 10 हजार लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि एक बड़ी आबादी इस बाढ़ के कारण समुद्र में बह गई। हर तरफ शहर में मलबा है और इसमें सिर्फ लाशें निकल रही हैं।

**त्रिपोली:** पूर्वी लीबिया के डर्ना शहर में रविवार को आई विनाशकारी बाढ़ से हजारों लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अकेले डर्ना शहर में 11,300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10,100 से ज्यादा लोग लापता हैं। शहर अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा जो बच गया और एक हिस्सा जहां कोई नहीं बचा। शहर के बाहर 170 लोगों की मौत हुई है। तारेक फहेम नाम का शख्स शनिवार की देर रात लीबिया की डर्ना घाटी में बांध के पीछे पानी भरने का वीडियो बना रहा था। रात में डेढ़ बजे तक तूफान डेनियल सिर्फ बारिश और तूफान था। एक घंटे में जब तक वह घर पहुंचता उसे पता चला कि बांध टूट गया और उसकी सड़कों पर पानी भर गया है।

उसने बताया कि पानी इतना ज्यादा था, जब वह कारों से टकराता तो ऐसा लगता जैसे भूकंप आ रहा है। वह अपने परिवार के साथ छत पर चला गया। यहां भी वह सब वाटर टैंक पर चढ़ गए। उसने अपने पड़ोस के घरों

को लेकर कहा कि ग्रांड फ्लोर पर रहने वाले शायद सिर्फ एक फीसदी लोग ही जिंदा बचे हैं। उसने कहा कि जब पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हुआ तो वह अपने पड़ोसियों को देखने के लिए नीचे गया। लेकिन वहां सड़कों पर एक मीटर तक कीचड़ भरा था। उसने कहा कि आसपास की 15 इमारतों में 33 लोग मारे गए।

**डैम टूटने से आई बाढ़:** शहर के बाहर बने दो डैम टूट गए, जिनके कारण एक विनाशकारी बाढ़ आई। माना जा रहा है कि सैकड़ों लोग बाढ़ के कारण समुद्र में बह गए। बचावकर्मी ढही हुई इमारतों में जीवित बचे लोगों की तलाश में हैं। हालांकि लोगों के बचने की उम्मीद कम है। उन्हें अब तक सिर्फ शव ही मिले हैं। सीमेंट के मलबे के नीचे और भी शवों के दबे होने की आशंका है।

**समुद्र से निकाले गए शव:** अंतरराष्ट्रीय सहायता और बचाव अभियान धीरे-धीरे आ रहे हैं, लेकिन तबाही का पैमाना जिस हिसाब से है, उसमें यह बहुत कम है। लीबिया के अलग-अलग हिस्सों के स्थानीय स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने तत्काल वह किया, जो कर सकते थे। अब्देल वहाब हारून (21) का कहना है कि उन्होंने रविवार को समुद्र से 40 शवों को निकाला। उन्होंने उस समय के हालात बताते हुए कहा, 'हर जगह लाशें थीं। कुछ महीने के बच्चे, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं। 30-40 लोगों का परिवार पूरा खत्म हो गया।'

## यूक्रेन ने भारतीय हीरा कंपनी को 'इंटरनेशनल वॉर स्पॉन्सर' बता लगाया प्रतिबंध, यह जी20 का बदला तो नहीं?

यूक्रेन ने रूस की मदद करने के आरोप में भारत की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक को प्रतिबंधित कर दिया है। यूक्रेनी भ्रष्टाचार निवारण एजेंसी ने कहा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी हीरा विनिर्माण और निर्यात कंपनियों में से एक श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स को युद्ध के अंतरराष्ट्रीय प्रायोजकों की सूची में शामिल किया है।

यूक्रेन ने एक भारतीय हीरा कंपनी को युद्ध के अंतरराष्ट्रीय प्रायोजकों की सूची में शामिल

किया है। यूक्रेन का मानना है कि भारत की यह कंपनी युद्ध के बीच रूस की आर्थिक मदद कर रही है। इसे यूक्रेन की भारत के खिलाफ खोज भी बताया जा रहा है। यूक्रेन चाहता था कि भारत जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उसे बुलाए और अपने मंच से रूस के खिलाफ जहर उगलने की अनुमति दे। भारत ने यूक्रेन के इस अनुरोध को ठुकरा दिया और जी-20 के साझा घोषणापत्र से भी रूस को बतौर आक्रामककारी शामिल नहीं किया। इस पर यूक्रेन ने उस वक्त कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन का यह एक्शन भारत के खिलाफ उसी खोज का परिणाम है।

**यूक्रेन का दावा-** रूस से ज्यादा हीरा खरीद रही भारतीय कंपनी

यूक्रेन की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण एजेंसी (एनएपीसी) ने इस साल रूस के साथ कथित वाणिज्यिक लेनदेन के लिए एक प्रमुख भारतीय हीरा निर्यातक को युद्ध का अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक बताया है। एनएपीसी ने एक बयान में कहा उसने दुनिया की सबसे बड़ी हीरा विनिर्माण और निर्यात कंपनियों में से एक श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स (एसआरके) को "युद्ध के अंतरराष्ट्रीय प्रायोजकों" की सूची में शामिल किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि इस कंपनी ने 2021 में खरीदे गए मात्रा की तुलना में 2023



में रूस से हीरे की खरीद लगभग तीन गुना कर दी है।

**कंपनी का रूस-यूक्रेन युद्ध से कोई संबंध नहीं-** यूक्रेनी एजेंसी ने दावा किया कि श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स ने 2023 की पहली छमाही में 132 मिलियन डॉलर मूल्य के रूसी हीरे खरीदे, जबकि पूरे 2021 में उसने रूस में 59 मिलियन डॉलर मूल्य के हीरे खरीदे। इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेनी एजेंसी का वर्गीकरण भारतीय कंपनी को कैसे प्रभावित करेगा। श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एसआरके एक्सपोर्ट्स वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी हीरा प्रसंस्करण फर्मों में से एक है, जो डी बीयर्स, आर्कटिक कैनेडियन डायमंड कंपनी और रियो टिटो जैसे पश्चिमी वैश्विक दिग्गजों से कच्चे हीरे की सोर्सिंग करती है।

**हीरा का सबसे बड़ा मैनुफैक्चरर है भारत-** विश्व के लगभग 95 प्रतिशत हीरे भारत में बनते हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण एजेंसी के मुताबिक श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स का सालाना राजस्व 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह भारतीय कंपनी कच्चे हीरे प्राप्त करने के बाद, कटिंग, पॉलिशिंग और उनके क्लास को निर्धारित कर फिर उनका निर्यात करती है। हालांकि यह कंपनी रूसी कंपनी अलरोसा से कुछ कच्चे हीरों का आयात करती है, जो मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक कंपनी है।

पेज 1 शेष

## भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व यूपी में दरखल अंदाजी बंद करे !

भाजपा को जीतना ही है, इसलिये वो भाजपा को वोट देते रहे। यूपी में कांग्रेस और बसपा बेहद कमजोर है। सपा सुप्रीमों कई उप-चुनावों में निकले तक नहीं। चाचा-भतीजे तक में कलह है तो ऐसे में भाजपा को सपा कैसे हरा सकेगी?

घोसी के चुनाव और इससे पहले मैनपुरी में प्रचार मे सपा ने ऐसी धारणाएं तोड़ दी। अखिलेश यादव और शिवपाल ने मिलकर जमीनी संघर्ष किया। इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हुये तो भाजपा को भारी मतों से हराना संभव हो गया। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए कम से कम हलवा तो नहीं हैं। कई राज्यों में कई- कई बार की सरकारें, दस साल से केंद्र की सरकार, जनता की खूब सारी अपेक्षाएं और अति अपेक्षाएं, एंटी-इनकम्बेंसी के खतरों का पहाड़...। महंगाई, बेरोजगारी और मुकाबले के लिये सामने खड़ा विपक्षी एकता वाला इंडिया गठबंधन। फिर भी भाजपा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिये आश्वस्त हैं? इस आत्मविश्वास के दो सबसे बड़े कारण हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकप्रिय चेहरा। दूसरा कारण योगी के उत्तर के 80 लोकसभा सीटें। भाजपा, भाजपा प्रशंसक और राजनीतिक पंडित मानते रहे हैं कि यदि विपरीत कारणों से आगामी लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों से भाजपा की लोकसभा सीटें कम भी हो जाती हैं तो अस्सी सीटों वाली यूपी की बड़ी जीत इसे कवर कर लेगी।

यूपी को रिजर्व कोटा या इमरजेंसी कोटा माना जा रहा है। गाड़ी पंचर होने की स्थिति में स्टेपनी रखी जाती है। स्टेपनी भी डेंट लगी हुयी हो तो गाड़ी कभी भी रुक सकती है। इस डेंट को पेट करना बेहद जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा का मजबूत किला है। सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा शरीर है तो यूपी इसकी आत्मा है। सनातनियों की भावनाएं और आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि यहां श्री रामजन्म स्थल भी है, श्री कृष्ण स्थली मथुरा भी है और भोलेनाथ की काशी भी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण रामभक्तों के अरमानों को पूरा कर रहा है। भगवानों की जन्मस्थली की पवित्र भूमि भाजपा की सियासत के लिये बेहद उर्वरक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी ने नौ साल पहले गुजरात छोड़ काशी के लोकसभा श्रेत्र को अपनाया।

सनातन धर्म के प्रहरी कहे जाने वाले एक संत, महंत योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो सोने पर सुहागा हो गया। सूबे की अच्छी-खासी आवाज मानती है कि योगी सरकार ने पुरानी जटिल समस्यायें और खतरे समाप्त कर दिये। दंगा मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश में लव जेहाद, तुष्टिकरण समाप्त हो गया। महिलाएं-बेटियां सुरक्षित हो गयीं।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यदि लगता है कि यूपी लोकसभा चुनाव में नैया पार कर लेगी तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड करना होना। बिना किसी दखल अंदाजी के पार्टी ज्वाइनिंग से लेकर टिकट बंटवारे में यूपी नेतृत्व पर सब कुछ छोड़ देना चाहिये। यूपी बदल गया है, यहां जातियों के नेताओं के गुलदस्ते से कहीं ज्यादा आकर्षित योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। विभिन्न जातियों के विश्वास को जीतकर सनातनियों की एकता का गुलदस्ता तैयार करने वाले योगी यूपी पूरब, पश्चिम से लेकर उत्तर, दक्षिण, अवध, बुंदेलखंड...पर विजय के लिये सक्षम है।

## लोकसभा चुनाव : यूपी की सियासत में 'मुल्ला' और 'चलनी' पर छिड़ गयी रार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमला बोलते हुये कहा कि उप मुख्यमंत्री की बचकानी हरकत दिखा रही है कि उनके पास राजनीतिक संस्कार नहीं है। भाजपा की खासियत यही है कि 'वहां पर सूप तो सूप चलनियां और ज्यादा बोलती हैं'...। कहा कि 'भाय ने उन्हें बिना योग्यता के उन्हें उच्च पद पर बिठा दिया है'। उन्हें कम से कम मुंह खोलते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये। अजय राय यहीं नहीं रुके...। कहा कि हम दोनों की पैदाइश एक ही वर्ष 1969 की है। पांच बार विधायक रहा व प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज भी सत्ता के शीर्ष दुगों से टकरा रहा हूं। मैं लोकतांत्रिक संघर्ष की इसी राजनीतिक पहचान पर जीता हूं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की ओर से सनातन धर्म की रक्षा को लेकर आइएनडीआइए को घेरने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री को घेरा। कहा कि सनातन धर्म की बातें करते समय

उप मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिये कि सनातन धर्म के संतों के आंदोलन में मुझे जेल भेजा गया। इसी सनातन धर्म की रक्षा के मामले में रासुका लगाया गया। बाद में अदालत ने मुझे बरी किया। संत समाज के आंदोलन से जुड़े उस मुकदमे में उन्हीं की सरकार ने केवल एक अजय राय को छोड़ सभी संतों एवं आंदोलन में शामिल राजनीतिक एवं अन्य लोगों के विरुद्ध केस वापस लिया है। राजनीतिक विद्वेष में डूबी इस सरकार की रीति-नीति, सनातन समाज ही नहीं सर्व समाज से जुड़े समस्त मुद्दों पर कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी।

बात जो भी हो, चुनाव करीब आते-आते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक, जुबानी रार की रफतार बढ़ती ही जायेगी। इन्हें इससे मतलब नहीं कि उनकी जुबानी जंग से अवाम के बीच क्या संदेश जायेगा, क्योंकि इन्हें तो चाहिये सिर्फ सत्ता...। देखते जाईये 'मुल्ला' और 'चलनी' के बाद क्या-क्या आता है...।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक संपादक दिव्या श्रीवास्तव गोल्डन लाइन प्रेस 510/115, न्यू हैदराबाद, फूलवाला पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है। कार्यालय पता- 1288/89 अंसल आंगन आशियाना, लखनऊ। ई मेल-sanjaysrivastava.ss26@gmail.com, मोबाइल नंबर-8317011531, सभी प्रकाशित लेख की जिम्मेदारी संबंधित संवाददाता की होगी। किसी भी लेख से स्वामी, मुद्रक, संपादक से कोई मतलब नहीं होगा। पीआरबी एक्ट के तहत इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवम संपादन हेतु उत्तरदाई तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ के अधीन होंगे। RNI No. UPHIN/2014/58463



